



2026:AHC:61626

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. कि धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 11827/2026

सैयद अनवर कमाल

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता

: अरविन्द प्रबोध दुबे, गुफरान खान, रवि सिंह

विपक्षी(यों) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 74

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत यह आवेदन आवेदक द्वारा अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), न्यायालय संख्या 1, गोरखपुर में लंबित शिकायत मामला संख्या 52975 वर्ष 2024 (अनिल कुमार तिवारी बनाम सैयद अनवर कमाल), धारा 138 एन.आई. एक्ट, थाना कैंट, जिला गोरखपुर में पारित सम्मन आदेश दिनांक 20.02.2025 को रद्द करने के लिए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि पक्षों के बीच पैसे का विवाद है और विपक्षी संख्या 2 ने आवेदक के खिलाफ एन.आई. एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि चूँकि पैसे के भुगतान के संबंध में



कुछ विवाद है, इसलिए समझौते के माध्यम से विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान की अच्छी संभावना है।

4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच., 2010 (5) SCC 663** में दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया है। संबंधित पैराग्राफ संख्या 17, 18 और 19 नीचे उद्धृत किए गए हैं:

"17. हाल ही में प्रकाशित एक टिप्पणी में, अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं [उद्धृत: अरुण मोहन, धारा 138 के विषय पर कानून सुधार की दिशा में कुछ विचार, परक्राम्य लिखत अधिनियम-मामलों के हिमस्खलन से निपटना (नई दिल्ली: यूनिवर्सल पब्लिशिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 2009) पृष्ठ 5 पर]:

'... अपराध के अन्य रूपों के विपरीत, यहाँ सजा (जहाँ तक शिकायतकर्ता का संबंध है) प्रतिशोध लेने का साधन नहीं है, बल्कि धन का भुगतान सुनिश्चित करने का एक साधन अधिक है। शिकायतकर्ता की रुचि चेक के लेखक को जेल में देखने के बजाय मुख्य रूप से पैसा वसूलने में होती है। जेल की धमकी केवल वसूली सुनिश्चित करने का एक तरीका है। उस अभियुक्त के खिलाफ जो जेल की सजा काटने के लिए तैयार है, चेक धारक के पास उपाय के रूप में बहुत कम उपलब्ध है।

यदि हम एक तरफ दायर की गई उन शिकायतों की संख्या की जांच करें जो अंतिम निर्णय से पहले 'समझौता' या 'सुलह' कर ली गई थीं और दूसरी तरफ वे मामले जो निर्णय और दोषसिद्धि तक बढ़े, तो हम पाएंगे कि बड़ा हिस्सा सुलझ गया था और केवल बहुत कम संख्या में मामले जारी रहे।"

"18. यह काफी स्पष्ट है कि चेक बाउंस होने के अपराध के संबंध में, उपाय के प्रतिपूरक पहलू को दंडात्मक पहलू पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विद्वान अटार्नी जनरल द्वारा उठाई गई आशंकाओं के लिए कुछ समर्थन भी है कि चेक बाउंस के अधिकांश



मामलों में वास्तव में शमन के माध्यम से समझौता या सुलह की जा रही है, हालांकि मुकदमेबाजी के बाद के चरणों के दौरान, जिससे न्याय वितरण में अनुचित देरी हो रही है। यहाँ समस्या मुकदमेबाजों की उस प्रवृत्ति के साथ है जो अपने विवाद को हल करने के साधन के रूप में शमन को देरी से चुनते हैं।"

"19. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विद्वान अटार्नी जनरल का तर्क है कि वैधानिक मार्गदर्शन के अभाव में, पक्ष मजिस्ट्रेटों द्वारा शिकायतों पर संज्ञान लेने के तुरंत बाद विकल्प चुनने के बजाय अंतिम उपाय के रूप में शमन को चुन रहे हैं। इस तरह के व्यवहार का एक स्पष्टीकरण यह हो सकता है कि अभियुक्त व्यक्ति मुकदमेबाजी के विभिन्न चरणों के माध्यम से आगे बढ़ने का मौका लेने के इच्छुक हैं और फिर समझौते का रास्ता तभी चुनते हैं जब कोई अन्य रास्ता नहीं बचता है। हालांकि इस तरह के व्यवहार को मुकदमेबाजों के दृष्टिकोण से तर्कसंगत माना जा सकता है, लेकिन ठोस तथ्य यह है कि शमन चुनने में अनुचित देरी विभिन्न स्तरों पर अदालतों के समक्ष लंबित बकाये में योगदान देती है। यदि अभियुक्त मुकदमेबाजी के बाद के चरण में अपराध के शमन के माध्यम से सुलह या समझौता करने के लिए तैयार है, तो यह आम तौर पर शिकायतकर्ता के मामले में कुछ योग्यता का संकेत देता है। ऐसे मामलों में यह वांछनीय होगा कि पक्ष मुकदमेबाजी के शुरुआती चरणों के दौरान शमन का चुनाव करें। हालांकि, यदि अभियुक्त के पास कोई वैध बचाव है जैसे कि अन्य आधारों के बीच गलती, जालसाजी या ज़बरदस्ती, तो मामले को निर्दिष्ट मंचों के माध्यम से लड़ा जा सकता है।"

5. अधिवक्ता के अनुरोध के अनुसार, यह निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त आज से एक महीने की अवधि के भीतर प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता के माध्यम से नीचे की अदालत के समक्ष उपस्थित हो सकता है और समझौते के माध्यम से अपराध के शमन की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और चेक राशि का 10% जमा कर सकता है। ऐसा आवेदन दिए जाने पर संबंधित अदालत इस संबंध में कानून के अनुसार उचित कदम



उठा सकती है और अभियुक्त को आगे अवसर प्रदान करेगी जो इस दिशा में प्रयास करने के लिए आज से अधिकतम चार महीने की अवधि से अधिक नहीं होगा। इसके पश्चात, अदालत आज से पांच महीने की अवधि के भीतर विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दामोदर एस. प्रभु (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए आवश्यक आदेश पारित करेगी।

6. यदि आवेदक समझौते के माध्यम से अपराध के शमन के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उपस्थित होना होगा और मुकदमे का सामना करना होगा और अदालत अभियुक्त के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही करने और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कानून द्वारा अनुमत सभी आवश्यक कदम और उपाय करने के लिए स्वतंत्र होगी।
7. उपर्युक्त पांच महीने की अवधि में या आवेदन के आलोक में दिए गए निर्णय तक, जो भी पहले हो, अभियुक्त के खिलाफ कोई दंडात्मक उपाय नहीं अपनाए जाएंगे।
8. यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश केवल उस अभियुक्त के संबंध में पारित किया गया है जिसकी ओर से इस न्यायालय में धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत यह आवेदन दिया गया है।
9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ यह आवेदन निस्तारित किया जाता है।

(दीपक वर्मा, न्यायमूर्ति)

25 मार्च, 2026